आयात पर निर्भरता घटाना जरूरी : पीयूष गोयल

उद्योग मंत्री ने व्यवसायियों को 'मेड इन इंडिया' पर जोर दिया

इंजीनियरिंग निर्यात 116 अरब डॉलर तक पहुँच

नई दिल्ली, 8 सितंबर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत वैश्विक चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे देश को स्वदेशी भावना और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना होगा. वे 56वें ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड्स कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की कि वे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को अपनाएं और आयात पर निर्भरता को कम करें.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत हर वैश्विक चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इसके लिए देश को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ना होगा. उन्होंने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को प्राथमिकता दें और आयात पर निर्भरता कम करें. गोयल नई दिल्ली में आयोजित 56वें ईईपीसी इंडिया नेशनल अवार्ड्स समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कई देश अपने निर्यात पर रोक लगा रहे हैं, जिससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, ऐसे में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना आवश्यक है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत का इंजीनियरिंग निर्यात अब 116 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू चुका है. साथ ही, उन्होंने जीएसटी सुधारों, गुणवत्ता नीति, और स्थिरता प्रयासों की भी सराहना की, जो भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई अंतरराष्ट्रीय देश अपने निर्यात पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जिससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है. ऐसे में स्थानीय निर्माण क्षमता और घरेलू नवाचार को प्राथमिकता देना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है. गोयल ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि जहां 1955 में इसका मूल्य मात्र 10 मिलियन डॉलर था, वहीं अब यह आंकड़ा 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. उन्होंने भविष्य में इसमें और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई.

मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और कहा कि सरकार की नीति के तहत उत्पादन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों पर बल दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत अब स्थिरता के मामले में दुनिया के शीर्ष

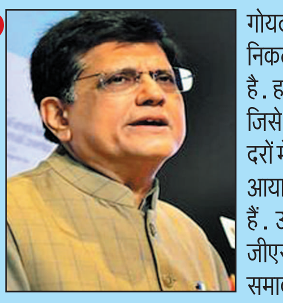

गोयल ने यह भी कहा कि भारत अब की सूची से बाहर निकलकर शीर्ष पाँच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है. हालिया तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जिसे उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि दरों में सुधार और कटौती से घरेलू मांग में सकारात्मक बदलाव आया है, जिससे रोजगार और आय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि कम जीएसटी दरों का लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुँचे ताकि समावेशी विकास संभव हो सके. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी उपस्थित रहीं. उन्होंने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में हुई प्रगति की सराहना की और सभी हितधारकों से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मज़बूत करने की अपील की.

उत्पादन में होगा भारी उछाल : जिंदल

जिंदल स्टील का कच्चा इस्पात उत्पादन बढ़ेगा 50 प्रतिशत

वर्ष-दर-वर्ष 50 वृद्धि की संभावना

मुंबई, 08 सितंबर 2025. जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य साझा करते हुए बताया कि कंपनी का कच्चा इस्पात उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में 50 प्रतिशत बढ़कर 12 मिलियन टन तक पहुँच सकता है.

उन्होंने इस लक्ष्य के पीछे संभावित विस्तार, कार्यान्वित परियोजनाओं और बेहतर परिचालन क्षमता को मुख्य आधार बताया. कच्चे इस्पात उत्पादन में बड़े पैमाने पर विस्तारजिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन

नवीन जिंदल ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कच्चा इस्पात उत्पादन 50 प्रतिशत तक बढ़कर 12 मिलियन टन तक पहुँच सकता है. यह वृद्धि पिछली वित्त वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण उछाल को दर्शाती है. कंपनी के परिचालन विस्तार और मापनीय क्षमता वृद्धि के साथ, यह उपलब्धि संभव हो पाएगी.

विस्तार की वजह से उत्पादन में वृद्धि

हाल ही में अपने आंगुल संयंत्र (ओडिशा) में विस्तार योजनाओं का उल्लेख किया है. इसके तहत वर्तमान क्षमता में विस्तार किया जा रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है. 13.7 मिलियन टन प्रति वर्ष की समग्र उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना, इसके लिए एक ठोस नींव है. विश्लेषकों का मानना है कि इस विस्तार की वजह से उत्पादन में भारी वृद्धि (ष्ट्वत्र) और बेहतर उत्पाद मिश्रण की संभावना है, जो में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा. का लक्ष्य है कि इसकी कटौती जाने वाले लागत और उच्च वर्ग के उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने से औपचारिक रूप से स्पष्ट लाभ हासिल हो सके.

पार्था डेंटल ने एलाइनर ट्रीटमेंट को बनाया किफायती

हैदराबाद, 8 सितंबर पार्था डेंटल, दक्षिण भारत की अग्रणी डेंटल चेन, ने अब एलाइनर-आधारित ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट को पहले से कहीं अधिक किफायती और सुविधाजनक बना दिया है.

अब यहां दो प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं — विश्व-प्रसिद्ध और इन-हाउस विकसित, जो मुस्कान सुधारने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत और बजट के अनुकूल बनाते हैं. दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद डेंटल चेन, अब मुस्कान सुधारने की सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफायती बना रही है. क्लिनिकल उत्कृष्टता और रोगी-प्रथम दृष्टिकोण के साथ, पार्था डेंटल अब दो एलाइनर विकल्प विश्व प्रसिद्ध और अपने अत्याधुनिक पेश कर रही है. इन एलाइनर्स की विशेषता यह है कि ये पारंपरिक धातु ब्रेसेज़ के मुकाबले पारदर्शी, आरामदायक और लाइफस्टाइल फ्रेंडली हैं. अब पार्था डेंटल पर शुरू होती है मुस्कान की यात्रा मुफ्त कंसल्टेशन, फ्री और 15,000 मूल्य के स्कैन के साथ, जो इलाज से पहले ही आपके भविष्य की मुस्कान दिखा देता है. इसके साथ ही, 90,000 तक की बचत और नो-कॉस्ट विकल्पों के साथ यह पहल उन सभी के लिए है जो स्टाइल और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं वह भी बजट में. पार्था डेंटल ने पेश किए दो एलाइनर विकल्प पुराने समय के असहज धातु ब्रेसेज़ की जगह अब पारदर्शी और रिमूवेबल एलाइनर्स ने ले ली है.

जियो की अपलोड- डाउनलोड स्पीड सबसे ज्यादा : ट्राई

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के सड़क और रेलवे रूट पर रिलायंस

भोपाल, रायपुर, 08 सितंबर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जुलाई 2025 में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के अनुसार, रिलायंस जियो ने मध्यप्रदेश के शहडोल से लेकर छत्तीसगढ़ के कोरबा और राजनांदगांव तक सड़क और रेलवे मार्ग पर कॉल कनेक्टीवी के साथ डाटा अपलोड और डाउनलोड स्पीड में सभी प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है.

ट्राई के आंकड़ो के मुताबिक रिलायंस जियो ने शहडोल से कोरबा और राजनांदगांव के बीच सड़क और रेलवे रूट पर सबसे ज्यादा औसतन 21.28 अपलोड स्पीड प्रदान की. वहीं,एयरटेल की 15.57,बीएसएनएल की 3.30 और वोडाफोन आइडिया की 15.43 अपलोड स्पीड रही. इसी तरह डाउनलोड स्पीड में भी जियो 228.09 के साथ नंबर वन पर रहा जबकि एयरटेल की 82.67,बीएसएनएल की 1.34, और वोडाफोन आईडिया की 29.78 डाउनलोड स्पीड रही. जियो की नेटवर्क लेटेंसी बेहद कम है, जो वीडियो कॉल, वर्चुअल मीटिंग्स और ऑनलाइन गेमिंग जैसे रियल-टाइम एप्लिकेशनों के लिए महत्वपूर्ण है. इसी तरह जियो की कॉल सेटअप सफलता दर सबसे ज्यादा 99.13 फिसदी रही जबकि समान अवधि में एयरटेल की 94.73,बीएसएनएल 85 और वोडाफोन आइडिया की दर 96.91 प्रतिशत रही.

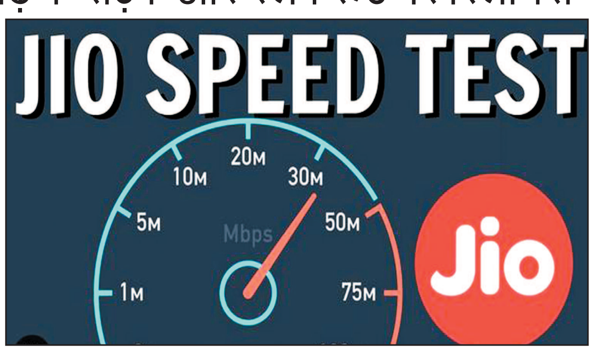

महीने भर चलने वाला सेलिब्रेशन प्लान

यह 349 रुपये से अधिक के प्लान वाले ग्राहकों के लिए है. 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में 2त्नक्च/प्रतिदिन और उससे ज़्यादा के लॉन्ग-टर्म प्लान पर जियो यूजर्स को मिलेगा अनलिमिटेड 5जी डेटा. जियो फ़ाइनेंस द्वारा जियो गोल्ड पर 2% अतिरिक्त डिजिटल गोल्ड साथ ही 3,000 रुपये के सेलिब्रेशन वाउचर इसमें शामिल होंगे. जियो हॉटस्टार और जियो सावन प्रो का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

अब भारत से वियतनाम की उड़ानें और भी सस्ती

5 से 30 नवंबर के बीच की यात्रा पर मिलेगा लाभ

बुक करें वियतजेट की टिकट, पाएं डबल बेनिफिट

नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता). वियतजेट एयर ने भारतीय यात्रियों के लिए एक शानदार ऑफर की घोषणा की है, जिसके तहत सीमित समय में टिकट बुक कराने पर 99 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है.

'9/9 फ्लैश सेल' के तहत दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, हैदराबाद और बेंगलुरु से वियतनाम के प्रमुख शहरों - हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और दा नांग — के लिए उड़ानों पर यह ऑफर लागू है. यह ऑफर 08 सितंबर रात 10:30 बजे से 09 सितंबर रात 9:30 बजे तक ही वैध रहेगा. यात्री 'सुपरसेल99' कोड का उपयोग कर इकोनॉमी क्लास टिकट पर भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही, 10 से 23 सितंबर के बीच बुकिंग करने पर 5 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए 20 किलोग्राम चेक-इन बैगेज भी मुफ्त दिया जाएगा. यह ऑफर वियतनाम से अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी लागू है.

भारतीय रेल का शक्तिशाली भविष्य

सहारनपुर, नागपुर और साबरमती में रखरखाव

6,300 टन तक माल खींचने में सक्षम

अहमदाबाद, 8 सितंबर 2025. भारतीय रेल ने माल परिवहन को मजबूत बनाने के लिए डब्ल्यूएजी-12बी नामक दो भागों वाली 25 हजार वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा वाली विद्युत मालवाहक इंजन विकसित की है.यह इंजन फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम और भारतीय रेल के संयुक्त प्रयास से तैयार हो रही है.

इसका निर्माण बिहार के मधेपुरा स्थित विद्युत इंजन कारखाने में हो रहा है.यह परियोजना 30 नवंबर 2015 को हुए खरीद और रखरखाव समझौते के तहत चल रही है, जिसमें 11 वर्षों में कुल 800 ऐसे इंजन बनाने का लक्ष्य है.

पहला इंजन वर्ष 2017 में कारखाने से निकला और उसे सहारनपुर डिपो में रखा गया.शुरू के 250 इंजनों को सहारनपुर में ही रखा गया, जबकि 251 से 500 तक के इंजनों को नागपुर शेड में स्थान दिया गया.अब 501 से 800 तक के 300 इंजनों के रखरखाव के लिए साबरमती शेड को चुना गया है. वर्तमान में साबरमती में 50 ऐसे इंजन रखे गए हैं. इस इंजन की लंबाई 38.4 मीटर है, वजन 180 टन जो 200 टन तक बढ़ाया जा सकता है.

रखरखाव में दक्षता बढ़ाने के लिए तीन विशेष मशीनें विकसित की गई हैं.पहली मशीन तीन चरण वाली इंजन के धुरी बक्से बदलने के लिए है, मॉडल संख्या आईई.3पीएच. धुरी सीके.50, क्षमता 50 टन, बंद ऊंचाई 360 मिलीमीटर, दबाव 550 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर.यह किसी भी विद्युत आपूर्ति वाली जगह पर काम करती है और प्राथमिक कुंडली वसंत भी बदल सकती है.

उच्च उत्पादन से कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली, 8 सितंबर 2025

आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है.क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में भारत में घर पर पकाई जाने वाली शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की लागत में क्रमशः 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

इस गिरावट का मुख्य कारण प्याज, आलू और दालों की कीमतों में आई भारी कमी है.भारत में उपभोक्ताओं को खाने-पीने के खर्च में राहत मिल रही है.

निसान मोटर्स 22 सितंबर से घटायेगी कीमत

कीमतों में 1,00,400 रुपये तक की कटौती की घोषणा की

नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता). निसान मोटर इंडिया ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए सोमवार को कीमतों में 1,00,400 रुपये तक की कटौती की घोषणा की. कंपनी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 22 सितंबर या उसके बाद की सभी डिलीवरी पर नयी कीमतें प्रभावी होंगी, हालांकि कम मूल्य पर बुकिंग अभी से शुरू हो गयी है.

उसने कहा कि इससे आगामी त्योहारी मौसम में ग्राहकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. इससे न केवल खुदरा मांग बढ़ेगी, बल्कि इससे वाहन उद्योग को नयी ताकत भी मिलेगी. दरों में बदलाव के बाद नयी निसान मैग्नाइट विसिया एमटी अब छह लाख रुपये से भी कम में उपलब्ध है. इससे देश की सबसे सुरक्षित एवं किफायती बी-एसयूवी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है.

नयी निसान मैग्नाइट एन-कनेक्ट सीवीटी और नयी निसान मैग्नाइट कुरो स्पेशल एडिशन सीवीटी संस्करण की कीमत भी अब 10 लाख रुपये से कम होने का अनुमान है. इससे आकर्षक कीमत पर एडवांस्ड फीचर्स एवं प्रीमियम की चाहत रखने वाले ग्राहकों को बेहतर मूल्य मिलेगा.

समाचार विशेष

मराठा आरक्षण देकर फंस गए फडणवीस!

ओबीसी नाराज, महायुति पर मंडराया नया सियासी संकट

मुंबई. महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समाज की आरक्षण मांग को स्वीकार कर मनोज जरांगे को शांत कर दिया है, लेकिन अब ओबीसी समाज की नाराजगी बढ़ती जा रही है. ओबीसी समुदाय के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और कोर्ट में लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया है. जिस तरह मराठा समाज को साधकर बीजेपी ने राहत पाई थी, अब ओबीसी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की मांग को मानते हुए फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गजट् लागू कर मराठा समाज को कुनबी जाति का दर्जा देकर बड़ा दांव चला है. कुनबी जाति पहले से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में शामिल है. ऐसे में मराठा समाज अब मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ ले सकेगा.

मराठा समाज की मांग मानकर बीजेपी ने ओबीसी समाज की नाराजगी को आमंत्रित कर लिया है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने अब अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है. ओबीसी समाज की नाराजगी को देखते हुए फडणवीस सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है. ओबीसी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लिया. इसके बाद उन्होंने खुलकर फडणवीस सरकार के फैसले का विरोध किया. बैठक से पूर्व वे उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मिले और स्पष्ट किया कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने से आरक्षण का संतुलन गड़बड़ा जाएगा. भुजबल ने मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र देने के सरकारी निर्णय के खिलाफ अदालत का रुख करने की बात कही है.

मराठा आरक्षण पर कानूनी लड़ाई की तैयारी

भुजबल ने कहा कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री फडणवीस मराठा समाज को लेकर ऐसा निर्णय लेंगे. वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और कैबिनेट उप.समिति ने आरक्षण का निर्णय लेने से पहले न तो कैबिनेट को विश्वास में लिया और न ही ओबीसी समाज से विचार.विमर्श किया.

क्या ओबीसी समिति से खत्म होगी नाराजगी

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यह समिति ओबीसी वर्ग के लिए विकासात्मक नीतियों पर सुझाव देगी. यह राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेगी और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी. साथ ही यह समिति ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेगी और आरक्षण से संबंधित सभी प्रशासनिक और वैधानिक पहलुओं का समन्वय बनाए रखेगी. अदालत में लंबित मामलों में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं से भी यह समिति तालमेल रखेगी और आवश्यक निर्देश देगी. सरकार इसे ओबीसी की नाराजगी दूर करने की दिशा में एक प्रयास मान रही है.

राजद की होशियारी पर राहुल की चाल भारी

पटना. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का एक अघोषित उद्देश्य सीटों का दबाव भी रहा. पिछली बार राजद ने कांग्रेस को लगभग तीन दर्जन वैसी सीटें भी थमा दी थीं, जहां पिछले तीन-चार चुनावों से उसकी भी दाल नहीं गल रही थी. हार स्वाभाविक थी. स्ट्राइक रेट बिगड़ा तो कांग्रेस को जब-तब लताड़ भी लगी.

वामदलों, विशेषकर भाकपा-माले, को अपना अनुचर बनाकर राजद आखिरी निर्णय के लिए तैयार बैठा था, लेकिन राहुल की इस यात्रा ने उसकी सोची-समझी रणनीति में अड़ंगा लगा दिया है. अपनी मांग से कम सीटों पर कांग्रेस राजी होती है, तो भी पसंदीदा सीटों से कोई समझौता नहीं करेगी. सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए महागठबंधन की समन्वय समिति 15 सितंबर को फिर माथापच्ची करेगी.

विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से लेकर साझा चुनावी रणनीति तक के लिए समन्वय समिति भी कांग्रेस के दबाव में ही बनी थी. तेजस्वी यादव को उसकी कमान मिलने से राजद आश्वस्त हुआ, तो कांग्रेस भी सतर्क रही. समिति की अब तक पांच दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बात दावेदारी वाली सीटों की सूची साझा करने से आगे नहीं बढ़ी. कांग्रेस की अपेक्षा थी कि अंदरखाने ही सही, सीटें चिह्नित हो जाएं, ताकि चुनावी तैयारी हो सके. इसमें राजद की आनकानी का एक बड़ा कारण नए सहयोगियों की आवक की संभावना थी.

राहुल ने अनुभूति कराई कांग्रेस में दम की

बिहार की परिक्रमा कर राहुल ने यह अनुभूति करा दी कि कांग्रेस में अब भी कुछ दम है. इस यात्रा का हर महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस ने लिया और शेष घटक दलों ने उसका अनुसरण किया. इसी तरह कांग्रेस सीट शेयरिंग में भी निर्णायक भूमिका चाह रही. बहरहाल, कांग्रेस की देखादेखी वीआईपी आदि दूसरे घटक दलों ने भी सीटों की लंबी सूची पेश कर दी है. राजद उधेड़बुन में है. अभी तो एनडीए में सीट शेयरिंग की प्रतीक्षा में बात आगे टाली जा रही, लेकिन चुनावी अधिसूचना के बाद हीलाहवाली नहीं चलेगी. सितंबर मध्य में अधिसूचना जारी हो सकती है.

विशेष

क्या माइनस बीजेपी-राजद समीकरण में है दम?

राहुल की बढ़ती ताकत फूलाएगी तेजस्वी की सांसें

पटना. वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी की नजरों में बिहार की प्राथमिकता तो दिखी ही, साथ ही इसके पुरजोर विपक्ष के रूप में कांग्रेस का एक नया चेहरा भी दिखा.

राहुल गांधी ने न केवल नीतीश नीत सरकार के आगे नई चुनौती पेश की, बल्कि यह तेजस्वी यादव के लिए कहीं बड़ी चुनौती न बन जाए. इतना भर नहीं, कांग्रेस ने इस वोटर अधिकार यात्रा में खुद को बीजेपी के बरक्स मुख्य विरोधी पार्टी के रूप में खड़ी करने में भी सफलता हासिल की है.

17 अगस्त को रोहतास ज़िले में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई. राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम के तहत बिहार में 15 दिन रहे. वोट अधिकार यात्रा के दौरान, बीते 16 दिनों में राहुल बिहार के 25 जिलों और 110 विधानसभाओं से गुजरे और 1300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने महागठबंधन के सहयोगियों के साथ की. इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ खुली जीप में राजद नेता तेजस्वी यादव, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी रहे. सबसे बड़ी बात इस यात्रा की रही कि चिलचिलाती धूप में भी राहुल गांधी समेत तमाम महागठबंधन के नेताओं का हौसला पस्त नहीं हुआ.

कांग्रेस का एक नया चेहरा दिखा

वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि वोटर पद यात्रा से कांग्रेस की अलग तस्वीर दिखी. लेकिन इस यात्रा में कांग्रेस का जो आत्मविश्वास बढ़ा है, वह राष्ट्रीय जनता दल के आगे नतमस्तक रहने वाला नहीं रहा. इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुस्लिम, दलित और सवर्ण के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है. यह संकेत बीजेपी के सामने नई चुनौती रख तो दी है, पर यह राजद के लिए भी कम चिंता का विषय नहीं है. हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस रास्ते पर कांग्रेस आगे बढ़ रही वह किसी नए राजनीतिक समीकरण की और बढ़ते दिख रहा है.

अखिलेश की पार्टी बिहार में नहीं लड़ेगी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार में विपक्षी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए. वे लालू प्रसाद के गृह जिला छपरा भी गए और वहां लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उनके और राहुल के साथ यात्रा में शामिल हुईं.

बाद में अखिलेश यादव ने दिल्ली में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से मुलाकात की. उन्होंने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए. उसके बाद कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि विपक्षी महागठबंधन् का समर्थन करेग ध्यान रहे सपा पहले बिहार में चुनाव लड़ती रही है. उत्तर प्रदेश से लगते इलाकों में उनके उम्मीदवारों को वोट भी मिल जाते थे. लेकिन जब से तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं और मुलायम सिंह के परिवार से लालू परिवार का रिश्ता जुड़ा है, तब से सपा पीछे हट गई. इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन अखिलेश यादव बिहार में प्रचार करेंगे. उनके प्रचार से राजद, कांग्रेस के साथ साथ पूरे महागठबंधन को मुस्लिम और यादव वोट के और एकजुट होने की उम्मीद है.